place in Karnataka. I would also like to know whether the monopoly houses have submitted proposals for setting up polyster units in the joint sector? If so, may I know whether they have been issued any letters of intent and whether the Karnataka Government has come forward with a proposal to have the unit in the joint sector? What is the latest position so far as the implementation of this scheme in Karnataka is concerned?

SHRI P. C. SETHI: As I have said, the letter of intent gives the option to the State Government to have it in the joint sector within the conditions stipulated in he letter of intent. As yet we have not received any proposal in this connection from the Karnataka Government. Except from Orissa Government, no proposal from any State Government has been received.

Waiting List for Telephone connections in Delhi

*223. SHRI SAJJAN KUMAR:

SHRI R. L. P. VERMA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to lay a statement showing:

(a) whether there is a long list in Delhi of those who have been waiting for telephone connections for several years;

(b) if so, the reasons for not augmenting the capacity of telephone exchanges in Delhi; and

(c) the particulars of those in the waiting list of various telephone exchanges as also of those who have booked telephone connections upto 31st July, 1981 and Government's plans to provide them telephone connections at the earliest?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI VIJAY N. PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) Due to shortage of financial and material resources, it has not been possible to augment the exchange to the extent needed to meet the demand fully.

(c) The particulars of the waiting list at various telephone exchanges at Delhi as on 1-8-81 is given in the annexure. The summary under the three categories was:—

O. Y. T.	9,139
Special	4,021
General	65,649
TOTAL	78,809

Since the list of waiting applicants is too long, it is not practicable to give the particulars of individual persons.

It is proposed to expand the existing exchanges and open new ones at Delhi to provide telephone connections to the applicants on the waiting list.

It is proposed to add.

23,000 lines in 1981-82

31,100 lines in 1982-83 and

41,800 lines in 1983-84

in Delhi Telephones.

It is expected that a majority of applicants on the waiting list as on 1-7-81 will be provided with telephone connections progressively by the end of 1983-84 except for certain pockets.

Statement

Statement of waiting list as on 1-8-81 *at exchange of Delhi Telephone District*

Sl. No.	Exchange	Waiting list as on 1-8-81			
		O.Y.T.	General	Special	Total
1	Shahdara East	203	2091	242	2536
2	Shahdara	282	2619	508	4409
3	Tis Hazari	216	4341	41	4598
4	Delhi Gate	222	3492	55	3769
5	Gaziabad—II	80	764	123	967
6	Gaziabad	81	1032	208	1321
7	Janpath	279	920	33	1232
8	Secretariat	475	207	16	698
9	Raj Path	309	679	69	1057
10	Connaught Place	..	..	..	..
11	Idgah	289	6298	111	6698
12	Jor Bagh	940	4235	257	5432
13	Okhla	572	2381	259	3212
14	Haus Khas	1255	4835	571	6661
15	Chanakayapuri	271	1230	93	1594
16	Nehru Place	872	1459	141	2472
17	Faridabad	329	1428	219	1976
18	Badarpur	..	..	..	..
19	Ballabgarh	26	429	131	586
20	Shaktinagar	641	9188	460	10289
21	Cantt.	177	263	24	464
22	Karol Bagh	609	5681	107	6397
23	Rajouri Garden	902	9688	229	10819
24	Alipur	1	11	1	13
25	Badli	11	134	16	161
26	Janakpuri	64	890	22	976
27	Bahadurgarh	10	128	27	165
28	Najafgarh	6	68	8	82
29	Nangloi	14	93	47	154
30	Narela	3	65	3	71
	TOTAL	9139	65649	4021	78809

श्री सज्जन कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि जैसा अभी उन्होंने बताया कि प्रतीक्षा-सूची में 78 हजार कुछ लोग हैं, उनको टेलीफोन देने का इनका कार्यक्रम तीन वर्ष तक 83–84 तक का बताया गया है। लेकिन आज जो दिल्ली में टेलीफोन की हालत है, जो मंत्री जी संसद में खड़े हो कर कहते हैं, दिल्ली के लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि यदि कोई टेलीफोन के लिए आवेदन देता है तो वह आवेदन चार साल तक पड़ा रहता है और उसको टेलीफोन नहीं मिलता है। जो मिलता भी है, तो यदि वह जामा-मस्जिद मिलता है, तो पार्लियामेंट में आकर मिलता है––इस प्रकार की टेलीफोन की हालत है। एक ओर आप कहते हैं आपके पास रा-मैटीरियल की कमी है, जिस के कारण आप उपभोक्ताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप ने ऐसे कौन से उपाय किए हैं, जैसे कि तीन साल का आपने टार्गेट रखा है कि सब लोगों को टेलीफोन दे देंगे, उन के लिए आप क्या साधन जुटायेंगे, कृपा कर के बताने का कष्ट करें ?

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन देने के वास्ते जो आई. टी. आई. रायबरेली की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उस को बढ़ा रहे हैं। सबस्टेंशियल इम्पोर्टस भी कर रहे हैं। पालघाट को कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। मगर उसके साथ यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इक्विमेंट एवेलेबिल हो जाने के बाद इम्मीडिएटली हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बिल्डिंग और एयर-कंडिशनिंग का प्रबन्ध करना पड़ता है, वह कार्यक्रम चल रहा है। अलग-अलग एक्सचेंजेज में नजदीक के भविष्य में रिलीफ देने वाले हैं। जैसे नेहरू प्लेस में तीन-चार महीने के अन्दर दस हजार लाइनें कमीशन हो जाने के बाद जो जोर-बाग, चाणक्य पुरी, हैदोज खास और नेहरू प्लेस के एक्सचेंजेज हैं, जो डिफीकल्ट हैं एक्सचेंज हैं, उन को रिलीफ दिया जा सकता है। शाहदरा में दो हजार लाइनें देने की कोशिश कर रहे हैं। तीस हजारी में दस हजार लाइनें एक साल के अन्दर जहां एक्सचेंज पाकेट्स हैं, वहां देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सज्जन कुमार : अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से एक यह जानकारी चाहता था कि सोशियल वर्कर की जो रजिस्ट्रेशन होती थी, क्या उस को बन्द कर दिया गया है? यदि बन्द कर दिया गया है, तो नए सिरे से विचार कर के उस को शुरू करेंगे ? दूसरे यह कि पब्लिक टेलीफोन्स के लिए कितने लोगों ने एप्लाई किया है और कितनों को आप देने जा रहे हैं ?

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, सोशियल वर्कर की कैटेगरी के लिए आपको स्पेशल दिया है, उस में स्माल-स्केल इन्डस्ट्री आता है, उस में सोशियल वर्कर भी आ जाता है, और उस में चार हजार एप्लीकेशंस वेटिंग लिस्ट में हैं। सोशियल वर्कर में यदि चार लोग लिख देते हैं कि सोशियल वर्कर है, वह डैफीनिशिन हम नहीं मानते हैं। चैरिटेबिल इन्स्टीचूशन्स, चेयरमैन, एम० एल० ए० आदि उस में अलग क्राइटेरिया है। . . . (व्यवधान). . . . दूसरी बात पी० सी० ओ० के बारे में है। यह इयर-आफ-दि-हैण्डीकेप है, इसलिए हम ने बहुत सी जगह हमने पी. सी. ओ. लगाए हैं और आगे भी अगर पार्लियामेंट के मैम्बर पब्लिक प्लेस के बारे में सुझाव देंगे जिस से पब्लिक को फायदा हो, तो हम उन जगहों को अवश्य चुनेंगे और स्थापित करेंगे।

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): I

may correct him. As far as social category is concerned, there was a provision that persons who claim to be doing social service are to be put in tht special category. Now there is no special category for persons who come in the social workers' category. In that place a new provision has come including persons of eminent reputation and something like that. This was done befroe. . . (*Interruptions*) "eminent personalities", that is the way it has come. . .(*Interruptions*) Please listen to me. I want to correct the record. Social service category is one of those categories which has been misused to a large extent. Anybody can come and say "I am a social worker". In a situation where there is a terrific demand for telephones, where the waiting list is mounting up, it will be a disservice and injustice to those people who are waiting in the queue to allow any such people to come in, in the name of social service, to the special category, across the legitimate claims of other people, who also have paid the money and are waiting for a connection. Therefore, considering that this is an area where misuse was taking place, that has been taken away. But the other important people, engineers, doctors, small-scale industrialists, all those are retained. I am only correcting the record. The rules have been amended to say that there will be no special category for the persons who come under the category "social workers", who are umpteen in number. They have been taken away.

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : दिल्ली में जो लोग जगह बदल कर दूसरी जगह चले जाते हैं उन के टेलीफोन के ट्रांस्फर में दिक्कत आ रही है । जैसे डिफेन्स कालोनी में रहने वाले लोग अगर सफदरजंग एन्क्लेव चले गये हैं तो उन के पुराने टेलीफोन को नई जगह पर लगाने में कितना समय लगेगा, चार-चौ महीने हो गये हैं, अभी तक नहीं लगा है ?

दूसरा प्रश्न--आप ने अभी स्पेशल कैटेगरी के बारे में बतलाया, लेकिन जो पार्लियामेण्ट मेम्बर के सैक्रेटरी हैं जो उन की कांस्टीचूएन्सी में काम करते हैं यदि उन के लिए पार्लियामेंट का मेम्बर सर्टिफाई करदें कि वह हमारी कांस्टीचूएन्सी में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यदि कोई अन्य सुविधा न दें तो इतना जरूर कर दें कि उन को जल्दी टेलीफोन मिल जाय ।

SHRI C. M. STEPHEN: There are a few exchanges, which have been declared frozen. In those exchanges, 90 per cent of the capacity is full and that is the maximum capacity which the exchange can take. If that limit has been crossed, if more connections are given, that exchange will not be able to take the load with the result that cross-connections take place and collaps would take place. Therefore, certain exchanges are declared as frozen. In the case of those exchanges, if a request for shift comes, the consideration is whether that exchange can accept new conectfons. When it is found that it is not acceptable, shifts cannot be permitted, because technically it is not feasible. This is the reason why it is being done.

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मेरे दूसरे सवाल का उत्तर नहीं दिया । पार्लियामेंट मेम्बर के सैक्रेटरी को टेलीफोन जल्दी देने के बारे में आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : आप ने अभी स्पेशल कैटेगरी के बारे में बतलाया--इस कैटेगरी में पहले आप ने एक हजार रुपये जमा करने के लिए कहा था फिर दो साल के बाद उस को 5 हजार रुपये कर दिया और अब 8 हजार रुपये कर दिया, लोगों का तीन-तीन साल से रुपया जमा है, उन को कोई ब्याज भी नहीं मिल रहा है, फिर भी उन को कनैक्शन नहीं दिया जा रहा है मैं चाहती हूं कि जो ऐसे लोग हैं

जिन का रुपया आप के यहां दो-तीन साल से जमा है उन को टेलीफोन कनेक्शन देने का कष्ट करें।

SHRI C. M. STEPHEN: The Special Category has nothing to do with the money that you are depositing. If you deposit Rs. 5,000—now it is Rs. 8,000-you will come in the OYT category, which itself is divided into two—General and Special. In the General Category, where you pay Rs. 1,000 there are two categories—General and Special. This has nothing to do with the money part of it.

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : पहले एक हजार था फिर पांच हजार हुआ और अब 8 हजार हो गया— इस को बढ़ाते जा रहे हैं।

SHRI C. M. STEPHEN: The learned Member may understand that Rs. 8,000 is for the OYT. For the General Category it is Rs. 1,000. In the General Category there are certain special classes who are entitled to special treatment. They are put in the Special Category. Suppose 1,000 lines are released. 40 per cent of the release will go to the Special Category. 25 per cent will go to the general category people. The rest will be reserved for the OYT category which is around 20 per cent or some thing like that and that also is divided between the general and the special in the OYT category. This arrangement is being made. The special categary is to meet the demands of persons who are answering social needs such as doctors and people of that type. Whosoever has the telephone need has got a social bearing and therefore, it is given a high categorisation. This system has been there for quite long and in those where misuse was taking place as I areas where misuse was taking place as I said, the rule in respect of that type of thing has been amended and real, genuine, special category of people have been given.

MR. SPEAKER: Question No. 226-Prof. Rup Chand Pal.

(Interruptions)

Revision of Rates of Subscription to News Agencies by official media

*226. PROF. RUP CHAND PAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to revise rate of payment of subscription to news agencies by the official media, radio and television; and

(b) if so, when the proposal is going to be implemented?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). As a result of the policy decision of the Government to abolish licence fee on one and two band radio sets, it has become necessary to modify the existing formula governing the payment of subscription by All India Radio and Doordarshan to the News Agencies. Government have appointed a Committee of officers to examine the question of payment of subscription to the News Agencies by All India Radio and Doordarshan in depth and to make suitable recommendations to the Government. The recommendations of the Committee are awaited. As soon as the recommendations of the Committee are available, the Government would decide on the new formula.

PROF. RUP CHAND PAL: Sir, may I konw from the hon. Minister whether it is not a fact that there is disparity between the English news agencies and those of Indian languages. What is the basis of the existing formula regarding payment by All India Radio and Doordarshan to different news agencies and who are the Members of the Committee that has been assigned to go into the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): Sir, I shall deal with the last point first. The Mem-